प्रफुल्ल कुमार दास और ओआरएस

वी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य।

7 अक्टूबर, 2003

[वी. एन. खरे, सीजे। , आर. सी. लाहोटी, बी. एन. अग्रवाल, एस. बी. सिन्हा और डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, जे. जे.]

सेवा कानूनः

वरिष्ठता-"आवंटन के वर्ष" की कानूनी कल्पना-उड़ीसा प्रशासनिक सेवा की प्रयोज्यता-दिसंबर, 1973 में वरिष्ठ शाखा के साथ पूर्ववर्ती कनिष्ठ शाखा का विलय-एकल एकीकृत संवर्ग का गठन-वरिष्ठता की नियुक्ति और आवंटन के संबंध में राज्य की लंबे समय से स्थापित नीति "आवंटन के वर्ष" के सिद्धांत का पालन करने के लिए थी-नित्यानंद कर के मामले में इस न्यायालय द्वारा मान्य-इस सिद्धांत के आधार पर कि क्या पूर्ववर्ती कनिष्ठ शाखा से एकीकृत सेवा में विलयकर्ताओं को सीधी भर्तियों के नीचे श्रेणीकरण सूची में रखा जा सकता है।

बाद में वर्ष 1973 के लिए पहचानी गई रिक्तियों के खिलाफ 1975 में नियुक्त किया गया-आयोजित, हाँ-1975 में नियुक्त लोगों के संबंध में संचालित "आवंटन के वर्ष" की कानूनी कल्पना जैसे कि उन्हें उस वर्ष नियुक्त किया गया था जब रिक्तियों की शुरुआत में पहचान की गई थी-उन्हें विलय से पहले 1973 में नियुक्त किया गया माना जाएगा-विलयकर्ता अपने आप में एक वर्ग थे, लेकिन पदोन्नत नहीं थे, इसलिए प्रत्यक्ष भर्तियों पर वरिष्ठता से इनकार किया जा सकता था, जिनका आवंटन वर्ष 1973 था-इसके अलावा, विलयकर्ता थे उनके ऊपर रखी गई सीधी भर्तियों की छोटी संख्या से शायद ही कोई प्रभावित हुआ-विलयकर्ताओं के लिए केवल कठिनाई 1992 के संशोधन अधिनियम को निरस्त करने का आधार नहीं हो सकती है, जिसमें निर्देशों को लागू करने की मांग की गई थी।

नित्यानंद कर के मामले में दिया गया-उड़ीसा प्रशासनिक सेवा, वर्ग-II (भर्ती) नियम, 1959-नियम 10 और 11-उड़ीसा प्रशासनिक सेवा वर्ग-II (पदोन्नति, स्थानांतरण और चयन द्वारा नियुक्ति)

विनियम, 1959-नियम 4 (2)-उड़ीसा प्रशासनिक सेवा, वर्ग-11 (अधिकारियों की नियुक्ति वैधता) संशोधन अधिनियम, 1992-धारा 2।

वरिष्ठता-अधिकार-धारितः यह मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि केवल एक नागरिक अधिकार है-वरिष्ठता के एक स्पष्ट अधिकार को राज्य द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ भी बदला या अस्वीकार किया जा सकता है-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 309।

302

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14-विधान-निरस्त करना

का-दायरा-आयोजितः किसी वैध कानून को निरस्त करने के लिए केवल कठिनाई एक आधार नहीं हो सकती है जब तक कि इसे भेदभावपूर्ण या अनुचित नहीं माना जाता है।

7 , 1972 , उड़ीसा प्रशासनिक सेवा II के साथ, जिसे बदले में उड़ीसा प्रशासनिक सेवा (ओ. ए. एस.) (वरिष्ठ शाखा) के रूप में जाना जाने लगा। 21 दिसंबर, 1973 के इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव के आधार पर इन शाखाओं के पूर्ण और अंतिम विलय के परिणामस्वरूप एक एकीकृत उड़ीसा प्रशासनिक सेवा वर्ग II का निर्माण हुआ। उप-कलेक्टर, सदस्यों के रूप में पूर्ववर्ती वरिष्ठ शाखा को जाना जाता था और इसके परिणामस्वरूप कनिष्ठ शाखा के उप-उप-कलेक्टरों को एकीकृत सेवा में अंतर-वरिष्ठता प्रदान की जाती थी ताकि निष्क्रिय कनिष्ठ शाखा का पहला नाम वरिष्ठ शाखा के अंतिम नाम के तुरंत नीचे रखा जा सके।

उड़ीसा राज्य की स्थापित प्रथा

इसके अधिकारियों की नियुक्ति और वरिष्ठता का आवंटन किया गया है

विलय, यानी 21 दिसंबर, 1973, को आवंटन के वर्ष के सिद्धांत के आधार पर प्रत्यक्ष भर्तियों के संबंध में वरिष्ठता से वंचित कर दिया गया था। 1973 के विलय के विशेष संदर्भ में आवंटन के वर्ष की अवधारणा को उच्च न्यायालय ने अनंत के मामले में बरकरार रखा था।

कुमार बोस *, जो निर्णय बाद में नित्यानंद कर * * के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उस मामले में दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए, उड़ीसा प्रशासनिक सेवा, वर्ग-II (अधिकारियों की नियुक्ति वैधीकरण) संशोधन अधिनियम, 1992 को उड़ीसा विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था।

वर्तमान अपील में विचार के लिए उठाए गए प्रश्न

और रिट याचिका यह है कि क्या उड़ीसा प्रशासनिक सेवा, वर्ग II (अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन अधिनियम, 1992, विशेष रूप से इसकी धारा 2 अमान्य है और क्या इसके आधार पर "आबंटन वर्ष" के सिद्धांत के अनुसार, कनिष्ठ शाखा से एकीकृत सेवा में विलयकर्ताओं को श्रेणीकरण सूची में न केवल वरिष्ठ शाखा के सदस्यों के नीचे रखा जा सकता है, बल्कि वर्ष 1973 के लिए चिन्हित रिक्तियों के लिए 1975 में बाद में नियुक्त प्रत्यक्ष भर्तियों के नीचे भी रखा जा सकता है।

रिट याचिका और अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने पकड़नाः 1.1 . परिणामस्वरूप, उड़ीसा प्रशासनिक की वैधता

सेवा, वर्ग-II (अधिकारियों की नियुक्ति वैधीकरण) संशोधन अधिनियम, 1992 और विशेष रूप से इसकी धारा 2, जो नित्यानंद कर के मामले में इस न्यायालय के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए उचित थी, को बरकरार रखा गया है। [324 - ई]

1.2 . यह स्पष्ट है कि न तो सरकार का संकल्प

दिसंबर 1973 और न ही 1992 के संशोधन अधिनियम की विवादित धारा 2 ने 1959 के भर्ती नियमों को स्पष्ट रूप से या निहित रूप से निरस्त कर दिया है। वास्तव में, प्रस्ताव स्वयं प्रासंगिक नियमों की ओर इशारा करता है, जिससे 1959 के भर्ती नियमों के निहित निरसन की संभावना समाप्त हो जाती है। इसी तरह, 1973 के प्रस्ताव में किसी भी तरह से उप-कलेक्टरों की भर्ती को समाप्त करने या भर्ती के वैकल्पिक तरीके का प्रावधान नहीं था, इस मामले में यह नहीं माना जा सकता है कि इसका प्रभाव 1959 के भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों को पूरी तरह से निरस्त करना था। यह 1978 तक नहीं था कि 1959 के भर्ती नियमों को उड़ीसा प्रशासनिक सेवा भर्ती नियम और पदोन्नति और प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए विनियम, 1978 के लागू होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। [315 - ई-जी]

* अनंत कुमार बोस बनाम। उड़ीसा राज्य, आकाशवाणी (1986) उड़ीसा 151 और

** नित्यानंद कर बनाम। उड़ीसा राज्य, [1990] सप। 2 एस. सी. आर. 644, संदर्भित।

1.3 . तब, विलय के परिणामस्वरूप 1973 के प्रस्ताव का कानूनी प्रभाव केवल यह था कि 1959 के भर्ती नियमों के नियम 4 के उपखंड (बी) में कोई आवेदन नहीं था, और तब इसे निहित रूप से निरस्त माना जा सकता था। [316 - डी]

2. प्रस्तुत करना और भी गलत है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने किया है,

कि संवर्गों के एकीकरण के आधार पर, आवंटन के वर्ष के सिद्धांत को अप्रासंगिक और महत्वहीन बना दिया गया था। वहाँ रह गए। विभिन्न स्रोत जिनसे ओ. ए. एस. II में भर्ती अन्य तुलनीय सेवाओं से स्थानांतरण सहित विलय के बाद की जा सकती है। किसी भी स्थिति में, भले ही यह माना जाए कि सीधी भर्ती अब भर्तियों का एकमात्र स्रोत होगी, जब तक कि ऐसी रिक्तियां थीं जिनकी पहचान विलय प्रस्ताव के लागू होने से पहले की गई थी, लेकिन जो खाली रह गई थीं, वर्ष की अवधारणा

आबंटन वास्तव में लागू रहा, हालांकि पहले की तुलना में अधिक सीमित रूप में। [216 - ई-एफ. आई.

3.1 . आबंटन वर्ष की अवधारणा इसके द्वारा प्रदान की जाती है

उड़ीसा प्रशासनिक सेवा वर्ग II के नियम 4 (2) में निहित स्पष्टीकरण (पदोन्नति, स्थानांतरण और चयन द्वारा नियुक्ति)

विनियम, 1959। आम तौर पर, और निश्चित रूप से, यह वास्तविक सेवा की अवधि है जो मामलों में निर्धारक कारक होनी चाहिए

पदोन्नति और परिणामी वरिष्ठता। हालाँकि, इस न्यायालय ने बाद में डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर एसोसिएशन मामले में अपने निर्णय के आधार पर इस सामान्य नियम के लिए एक अलग अपवाद बनाया है, जिसमें कहा गया है कि जहां कई लोगों की वरिष्ठता और निहित अधिकार वर्षों की अभ्यस्त प्रथा के माध्यम से एक नियम के अस्तित्व पर निर्भर हो जाते हैं, तो यह नियम, यदि कुछ लोगों के अधिकारों के लिए हानिकारक है, तो इसे तब तक तुच्छ नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह अव्यवहारिक या स्पष्ट रूप से मनमाना न हो। { 316 - जी, 317-बी-डी]

रोशन लाल टंडन बनाम। भारत संघ, [1968] 1 एस. सी. आर. 185 और डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन v. महाराष्ट्र राज्य,

[1990] 2 एस. सी. सी. 715, संदर्भित।

3.2 . नित्यानंद कर में इस न्यायालय ने प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग II में संविधान पीठ के पूर्व निर्णय पर सही ढंग से भरोसा किया

इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन, समय के भारी अंतराल और आवंटन के वर्ष की अवधारणा के अनुप्रयोग से जुड़ी प्रथा की लंबे समय से स्थापित पवित्रता को देखते हुए। [317 - जी-एच] पी. के. डीएएस बनाम।

राज्य

305

4. आबंटन वर्ष की अवधारणा को भी दिखाया गया है

व्यवहार्य, क्योंकि 1973 के विलय के बाद के परिदृश्य में सरकार के लिए विभिन्न स्रोतों से अधिकारियों की भर्ती के लिए खुला था, जिसमें तुलनीय सेवाओं से स्थानांतरण भी शामिल था, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं था। जब एक बार आवंटन के वर्ष की अवधारणा को बरकरार माना जाता है, तो यह मायने नहीं रखता कि O.S.A.S का पहला नाम पूर्ववर्ती O. A. S. के अंतिम नाम से तुरंत नीचे होगा। तथ्य की भौतिक बात यह है कि एक कानूनी कल्पना को अपनाने और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपने संवैधानिक कार्य का सहारा लेने के माध्यम से,

उड़ीसा राज्य के राज्यपाल ने वर्ष 1975 में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें दिसंबर 1973 के विलय प्रस्ताव के लागू होने से पहले वर्ष 1973 में चिन्हित रिक्तियों के लिए नियुक्त किया गया था। इस मामले में, आवंटन के वर्ष की कानूनी कल्पना 1975 में नियुक्त लोगों के संबंध में इस तरह काम करेगी जैसे कि उन्हें उस वर्ष नियुक्त किया गया था जब रिक्तियों की शुरुआत में पहचान की गई थी। दूसरे शब्दों में, उन्हें ओ. ए. एस. II के O.S.A.S के साथ विलय से पहले वर्ष 1973 में नियुक्त किया गया माना जाएगा, हालांकि उनकी सेवा की वास्तविक अवधि 1975 में ही शुरू होती देखी गई थी। [318 - डी-एफ}

5.1 . इसके अलावा विलय प्रस्ताव के आधार पर, के सिद्धांत

1959 के नियमों में निहित पदोन्नति को इस तरह बरकरार रखा गया था कि किसी विशेष वर्ष के पदोन्नत लोगों को उस वर्ष की प्रत्यक्ष भर्तियों से अधिक वरिष्ठता दी जाएगी। यह O.S.A.S के वे सदस्य हैं, जैसे कि वर्तमान याचिकाकर्ता, जो विलय प्रस्ताव (1970-73) से पहले के वर्षों में O.S.A.S के सामने आने पर पदोन्नति हासिल करने में असमर्थ थे, जो केवल इस तथ्य के आधार पर प्रत्यक्ष भर्तियों पर वरिष्ठता चाहते हैं कि वे अंतर्वर्धित सेवा के सदस्य हैं।

इस तरह के थोक एकीकरण को पूरे O.S.A.S को बढ़ावा देने के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह निष्कर्ष 1959 के भर्ती नियमों में निहित विभिन्न प्रावधानों द्वारा समर्थित है, मुख्य रूप से नियम 10 (7) और नियम 11। [318 - जी-एच, 319-ए]

5.2 . दिसंबर 1973 के विलय के बाद से, इसके अंतर्गत नहीं आता है

पदोन्नति के लिए विभिन्न मानदंड, इसे थोक नहीं माना जा सकता है

सभी O.S.A.S कर्मचारियों की पदोन्नति। जिन कथित कर्मचारियों को ओ. ए. एस. II में एकीकृत किया गया था, उन्हें अपने लिए एक वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए, लाभार्थी, जैसा कि वे हैं, एक ही उपाय के परिणामस्वरूप दोनों कैडरों का एकीकरण होता है।

[319 - एच, 320-ए] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2003] एसयूपीपी। 4 एस सी आर।

306 6. संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत, राज्य के राज्यपाल को ऐसी सेवाओं और पदों पर भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने का अधिकार है, जब तक कि

उस ओर से प्रावधान विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत किया जाता है।

विधायिका, या राज्य का राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, अपने विवेकाधिकार पर, वरिष्ठता का अधिकार प्रदान या विच्छेद कर सकता है। यह अनिवार्य रूप से नीति का विषय है, और निहित अधिकार का सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि राज्य ऐसे किसी भी प्रत्यक्ष अधिकार को बदल या अस्वीकार कर सकता है, भले ही वह चाहे तो पूर्वव्यापी प्रभाव के माध्यम से या सार्वजनिक हित में हो। [320 - बी-सी]

7. यह दावा कि ओ. ए. एस. II का लोप

वर्ष 1975 में भर्ती के लिए विज्ञापन, जिसमें केवल उड़ीसा वित्तीय और पुलिस सेवाओं में रिक्तियों का उल्लेख किया गया था, उत्तरदाताओं की सीधी भर्तियों की नियुक्तियों को रद्द करने का काम करेगा, अविश्वसनीय है। विज्ञापन जारी होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी उम्मीदवार ने चयन का निहित अधिकार हासिल नहीं किया है। इसके विपरीत, जब एक बार सरकार द्वारा वर्ष 1973 के लिए रिक्तियों की पहचान की गई थी, तो यह एक समय में एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र था।

अपने चयन का तरीका। तब, इस उद्देश्य के लिए जारी किए गए विज्ञापन में ओ. ए. एस. II की चूक का मात्र तथ्य अपने आप में नहीं होगा। प्रत्यर्थी प्रत्यक्ष भर्तियों की नियुक्तियों को निरर्थक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए राशि। [320 - एफ, जी-एच, 321-ए]

8.1 . इस तथ्य के आधार पर कि ओ. ए. एस. II में रिक्तियों की पहचान दिसंबर को प्रभावी विलय से पहले एक समय पर की गई थी

21 , 1973 , इन रिक्तियों को निश्चित रूप से एकीकृत संवर्ग में रिक्तियों के रूप में माना जाएगा। एक बार जब आवंटन के वर्ष की अवधारणा को वैध माना जाता है, तो कोई भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि 21 दिसंबर, 1973 को प्रभावी विलय के बावजूद, विलय प्रस्ताव से पहले पहचानी गई रिक्तियों को सरकार अपने विवेक से भरेगी। [321 - एफ-जी] 8.2 . आवंटन का वर्ष प्रदान करने के उद्देश्य से एक कानूनी कल्पना बनाई गई थी। इस तरह की कानूनी कल्पना को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। [321 - एच]

भावनगर विश्वविद्यालय बनाम. पालिताना शुगर मिल प्रा. लि. लिमिटेड और अन्य,

[2003] 2 एस. सी. सी. 111, पर भरोसा किया।

9.1 . के प्रयोजनों के लिए विलय प्रस्ताव का प्रभाव

वरिष्ठता के लाभों का आवंटन केवल इतना था कि पूर्ववर्ती 307

पी. के. डीएएस बनाम राज्य

O.S.A.S के सदस्य अब उन प्रत्यक्ष भर्तियों से वरिष्ठ के रूप में रैंक करेंगे जिनका सेवा में शामिल होने का वर्ष और आवंटन का वर्ष 1973 से बाद का था। दूसरे शब्दों में, दिसंबर 1973 में विलय के समय, O.S.A.S के उप-कलेक्टरों को न केवल पूर्ववर्ती O. A. S. II के उप-कलेक्टरों के नीचे की श्रेणीकरण सूची में रखा गया था, बल्कि उन अधिकारियों के नीचे भी रखा गया था जिनकी परिकल्पना पिछले वर्षों की रिक्तियों द्वारा की गई थी, लेकिन जिन्हें वास्तव में अभी तक भर्ती नहीं किया गया था। विलय का उद्देश्य स्वयं ओ. ए. एस. II में सीधी भर्ती को बंद करना नहीं था, और न ही यह चिन्हित रिक्तियों के प्रश्न को संबोधित करता था। [322 - जी-एच, 323-ए]

9.2 . वर्ष 1973 और अन्य वर्षों के लिए चिन्हित रिक्तियां

दिसंबर 1973 के विलय प्रस्ताव से पहले, अस्तित्व में रहा और आवंटन के वर्ष के सिद्धांत के अनुरूप सरकार द्वारा उचित रूप से भरा गया था। [323 - बी]

10. न्याय के हित में इस तथ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए कि

निष्क्रिय O.S.A.S से संबंधित सैकड़ों विलयवादियों की तुलना में प्रत्यर्थी प्रत्यक्ष भर्तियां संख्या में कम हैं।

उत्तरदाताओं को नुकसान होगा अगर उन्हें नीचे रखा जाए

श्रेणीकरण सूची में विलय नियुक्तियां, जबकि विलयकर्ता हैं

सीधी भर्तियों की कम संख्या से शायद ही कोई प्रभावित हो उनके ऊपर। किसी भी स्थिति में, 1959 के भर्ती नियम अपने आदेश में स्पष्ट हैं कि केवल एक विशेष वर्ष के पदोन्नत व्यक्ति ही

उस वर्ष की प्रत्यक्ष भर्तियों से ऊपर रखा जाए। वर्तमान याचिकाकर्ता

केवल विलयवादी होने के नाते, लेकिन के अनुसार बढ़ावा नहीं देता है

प्रासंगिक नियम और विनियम, पदोन्नति की स्थिति का दावा नहीं कर सकते हैं,

और इसलिए, सीधे नीचे की स्थिति में उचित रूप से रखा गया है भर्ती जिनका आवंटन वर्ष 1973 था। [323 - सी-ई]

11.1 . वरिष्ठता मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह केवल एक नागरिक अधिकार है

सही है। इस मामले में वरिष्ठता का अधिकार भी निहित या अर्जित नहीं था। सही है। इस मामले में, याचिकाकर्ता लाभ चाहते हैं जिसके लिए वे नहीं हैं

अन्यथा हकदार। विधायिका के पास पारित करने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र है एक उपयुक्त विधान जो अपने कर्मचारियों के साथ न्याय करेगा।

विवादित कानून के कारण संतुलन को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, इस न्यायालय के लिए यह अनुमति नहीं होगी कि वह इसे केवल अधिकार से बाहर घोषित करे

क्योंकि इससे याचिकाकर्ताओं को कुछ कठिनाई हो सकती है। एक मात्र

एक वैध कानून सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2003] एस. यू. पी. पी. को निरस्त करने के लिए कठिनाई एक आधार नहीं हो सकती है।

जब तक कि इसे भेदभाव की बुराई से पीड़ित नहीं माना जाता है या अनुचितता। इस प्रकार, एक वैध कानून को केवल तभी निरस्त किया जा सकता है जब इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर पाया जाए और अन्यथा नहीं। इस मामले में, संविधान का अनुच्छेद 14 आकर्षित नहीं है। [323 - जी-एच, 324-ए-बी।

11.2 . प्रत्यक्ष भर्तियों के संबंध में कोई कानून मौजूद नहीं था। विवादित अधिनियम के कारण, विधायिका ने हड़ताल करने की मांग की है

नाजुक संतुलन। मामले में प्राप्त तथ्य स्थिति की संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिनियम भेदभावपूर्ण प्रकृति का नहीं पाया गया है। [323 - ई-एफ]

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लेखन याचिका (सी) सं. 611

1992 .

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

के साथ

1993 का सी. ए. सं. 791।

उपस्थिति दलों के लिए सोली जे. सोराबजी, अटॉर्नी जनरल, पी. एन. मिश्रा, वीनू भगत, पी. गौर, एस. मिश्रा, आर. एम. पटनायक, अभिजीत सेनगुप्ता और अजय शर्मा।

न्यायालय का निर्णय इस प्रकार दिया गयाः

23.4.1991 भुवनेश्वर में उड़ीसा प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा 1986 के हस्तांतरित आवेदन No.402 में पारित किया गया। उक्त आवेदन में, यहाँ अपीलकर्ताओं ने, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादी संख्या पर निर्देश के लिए प्रार्थना की। 1 उन्हें निजी उत्तरदाताओं से ऊपर रखकर उनकी वरिष्ठता तय करना और उन्हें परिणामी कैरियर लाभ प्रदान करना। रिट याचिका में भी याचिकाकर्ताओं ने उड़ीसा प्रशासनिक अधिनियम को रद्द करने का अनुरोध किया है। सेवा वर्ग II (अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन अध्यादेश, 1992, जिसे बाद में अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, और यह घोषणा करने के लिए भी कि उक्त अध्यादेश (अधिनियम) याचिकाकर्ताओं के मामले में लागू नहीं है और किसी भी स्थिति में इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

पक्षों के बीच मूल विवाद की अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमता है

अधिनियम में परिकल्पित आवंटन का वर्ष। यह प्रश्न अनंत कुमार बोस बनाम में उड़ीसा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था। उड़ीसा राज्य, ए. आई. आर. (1986) उड़ीसा 151 जिसमें आवंटन के वर्ष के सिद्धांत के साथ-साथ पक्षकारों के संबंध में इसके अनुप्रयोग को भी बरकरार रखा गया था। उड़ीसा उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय नित्यानंद कर बनाम में विचार के लिए आया। उड़ीसा राज्य, [1990] सप। 2 एस. सी. आर. 644 और तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उनके विचारों की पुष्टि की।

उड़ीसा उच्च न्यायालय।

धारा 2 के आधार पर, उड़ीसा प्रशासनिक सेवा, वर्ग-II

(अधिकारियों की नियुक्ति वैधीकरण) अधिनियम, 1987 ("वैधीकरण अधिनियम") में इस तरह से संशोधन करने की मांग की गई है कि उड़ीसा में कुछ सीधी भर्तियां हों।

वर्ष 1973 के लिए प्रशासनिक सेवा, जिन्हें 1975 में नियुक्त किया गया था, को उन विलय भर्तियों के संबंध में सापेक्ष वरिष्ठता प्रदान की जाती है जो पूर्व सेवा के आधार पर उक्त सेवा में पैदा हुए थे।

उनके मूल संवर्ग, उड़ीसा अधीनस्थ प्रशासनिक का विलय 21 दिसंबर, 1973 को ओ. ए. एस., वर्ग-II (ओ. ए. एस. II) के साथ सेवा ("O.S.A.S".)।

रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ दीवानी याचिका में अपीलार्थी

अपील उड़ीसा अधीनस्थ सेवा वर्ग III के सदस्य थे, जिसे 7 जनवरी, 1972 को उड़ीसा प्रशासनिक सेवा II के साथ इसके प्रस्तावित और आंशिक विलय के बाद उड़ीसा प्रशासनिक सेवा (कनिष्ठ शाखा) के रूप में नामित किया गया था, जिसे बदले में उड़ीसा प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) के रूप में जाना जाने लगा। का पूर्ण और अंतिम विलय

21 दिसंबर, 1973 के इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव के आधार पर इन शाखाओं के परिणामस्वरूप एकल एकीकृत शाखा का निर्माण हुआ।

उड़ीसा प्रशासनिक सेवा वर्ग II। उप-कलेक्टर, के रूप में

कनिष्ठ शाखा को अंतिम नाम के तुरंत नीचे रखा जाएगा। वरिष्ठ शाखा।

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उड़ीसा राज्य की स्थापित प्रथा

इसके अधिकारियों की नियुक्ति और वरिष्ठता के आवंटन के बारे में

"आबंटन वर्ष" के सिद्धांत का पालन करने के लिए, जिसके द्वारा

पदोन्नति और परिणामी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2003] उप के उद्देश्यों के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति।

310 वरिष्ठता को वास्तविक नियुक्ति की तारीख के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि उस वर्ष के रूप में माना जाता है जिसके संबंध में मूल रूप से रिक्ति को भरने का प्रस्ताव किया गया था।

कथित प्रथा के अनुरूप, प्रतिवादी अधिकारियों को, वर्तमान उदाहरण में, उनके आवंटन के वर्ष के रूप में 1973 दिया गया था, हालांकि उन्होंने वर्ष 1975 में अलग-अलग तिथियों पर सेवा शुरू की। याचिकाकर्ताओं और अपीलकर्ताओं, विलयवादी होने के नाते जो जन्म में थे

विलय की तारीख 21 दिसंबर, 1973 को एकीकृत सेवा को आवंटन के वर्ष के सिद्धांत के आधार पर प्रत्यक्ष भर्तियों के संबंध में वरिष्ठता से वंचित कर दिया गया था।

1973 के विलय के विशेष संदर्भ में आवंटन के वर्ष की अवधारणा पर पहली बार उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित के संबंध में हमला किया गया थाः वे प्रत्यक्ष भर्तियां जिन्हें 1970 और 1971 को उनके संबंधित वर्ष के आवंटन के रूप में सम्मानित किया गया था, हालांकि वे समय के भौतिक बिंदु पर बाद की तारीख में उनकी वास्तविक नियुक्ति के आधार पर सेवा में पैदा हुए थे। अनंत कुमार बोस (उपरोक्त) मामले में उच्च न्यायालय ने चुनौती का खंडन किया और आवंटन के वर्ष के सिद्धांत को एक बाध्यकारी नियम के रूप में बरकरार रखा, जिसे लंबे वर्षों के व्यवस्थित अभ्यास के माध्यम से पवित्रता दी गई और इसे शामिल करने वाले विभिन्न नियमों और विनियमों के संदर्भ में उचित ठहराया गया। उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति की याचिका को तब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था।

अनंत कुमार बोस मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय

(ऊपर) को बाद में ऐसी ही परिस्थितियों में समर्थन मिलेगा जो नित्यानंद कर (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आई थीं। अनन्त कुमार बोस (उपरोक्त) मामले में उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों और निर्देशों को व्यावहारिक प्रभाव देने के लिए, उड़ीसा राज्य के विधानमंडल ने उड़ीसा प्रशासनिक सेवा, वर्ग II (अधिकारियों की नियुक्ति) अधिनियम, 1987 अधिनियमित किया। यह अधिनियम एक बार फिर उड़ीसा के उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय था, लेकिन अनंत कुमार बोस (ऊपर) में पूर्ण पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष याचिकाकर्ताओं के मामले को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपील के साथ-साथ नित्यानंद कर (ऊपर) में एक साथ सुनी गई तीन रिट याचिकाओं में यह विचार व्यक्त किया था कि उड़ीसा का निर्णय अनंत कुमार बोस (ऊपर) में उच्च न्यायालय सही और बाध्यकारी कानून था। यह न्यायालय, डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन v में अपने स्वयं के निर्णय पर और अधिक भरोसा रखता है। महाराष्ट्र राज्य, [1990] 2 एस. सी. सी. 715] ने यह विचार रखा कि एक अच्छी तरह से स्थापित 311 की पवित्रता है।

नियम को अस्थिर नहीं किया जाना चाहिए, और अनंत कुमार बोस (ऊपर) में उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में आवंटन के वर्ष का सिद्धांत भी उचित था। हालाँकि, अदालत ने अपील को खारिज करते हुए, प्रत्यक्ष भर्तियों में से एक द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, और 1987 के वैधीकरण अधिनियम के उस हिस्से को रद्द कर दिया, जो एक ओर उन प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच अंतर को प्रभावित करता था, जिनके आवंटन का वर्ष 1970 या 1971 था, और अन्य जिनके आवंटन का वर्ष 1972 था।

नित्यानंद कर (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में,

1972 को अपने आवंटन वर्ष के रूप में रखने वाली सीधी भर्तियां विलयकर्ताओं के सापेक्ष वरिष्ठता के पदों पर श्रेणीकरण सूची में रखे जाने के लिए समान रूप से हकदार होंगी, जो पहले उप-कलेक्टर और फिर ओ. ए. एस. के सदस्य थे। (कनिष्ठ शाखा)। उच्चतम न्यायालय ने नित्यानंद कर (उपरोक्त) मामले में स्पष्ट किया कि जिन प्रत्यक्ष भर्तियों को उनके आवंटन के वर्ष के रूप में 1973 दिया गया था, वे उनके निर्णय के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनसे संबंधित कार्यवाहियां तब आयोग के समक्ष लंबित थीं।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण।

याचिकाओं का निपटारा करने और उसके समक्ष अपील करने में, नित्यानंद कर

(ऊपर) इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" अतः यह स्पष्ट है कि ओ. ए. एस. द्वितीय श्रेणी संवर्ग इससे पहले

विलय ओ. ए. एस. के अधिकारियों को प्रचार चैनल प्रदान कर रहा था।

पता चला कि ओ. ए. एस. वर्ग III के विलयकर्ता न तो थे पदोन्नत करता है और न ही सीधे भर्ती करता है और खुद से एक वर्ग बनाता है।

राज्य सरकार के 1972 के प्रस्ताव में निर्णय लिया गया था कि अवशोषण के लिए प्रक्रिया पर प्रसार लेकिन दिसंबर, 1973 में,

तत्काल और एक बार के विलय का निर्णय लिया गया और उस पर कार्रवाई की गई। हम.

क्योंकि आवंटन का वर्ष विलयकर्ताओं के लिए वरिष्ठ था। एक बार 'आवंटन वर्ष' की अवधारणा और अनुप्रयोग को अनिवार्य रूप से बरकरार रखा जाता है।

1973 के ओ. ए. एस. वर्ग II की प्रत्यक्ष भर्तियां तथ्यों में और

परिस्थितियाँ विलयकर्ताओं से वरिष्ठ होती हैं। वे कुल ग्यारह हैं।

जैसा कि 16 तारीख की सरकारी अधिसूचना से प्रतीत होता है। फरवरी, 1976। होने का कोई औचित्य नहीं होगा

तृतीय श्रेणी की सेवा से विलयकर्ताओं को संयुक्त संवर्ग में लाया गया 312

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2003] एस. यू. पी. 4 एस सी आर।

दिसंबर, 1973 में, इन 1973 भर्तियों से वरिष्ठ होने के लिए उनकी संख्या पर्याप्त है जो केवल ग्यारह लोग हैं। दूसरी ओर, 1973 से लेकर ओ. ए. एस. तक की सीधी भर्तियों के बीच वरिष्ठता तय करने के मामले में औचित्य हो सकता है।

तृतीय श्रेणी के अधिकारियों को एक विशेष संख्या द्वारा द्वितीय श्रेणी में पदोन्नत करना और तत्कालीन प्रचलित प्रावधानों के अनुसार अंतर-वरिष्ठता तय करना। नियम "।

उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश को लागू करने के उद्देश्य से, उड़ीसा विधानमंडल ने विवादित अधिनियम, उड़ीसा प्रशासनिक अधिनियम, अधिनियमित किया। सेवा, वर्ग-II (अधिकारियों की नियुक्ति वैधता) संशोधन अधिनियम, 1992, जो न्यायिक समीक्षा के लिए हमारे समक्ष आया है।

1992 के संशोधन अधिनियम की धारा 2 से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने आवश्यक राहत के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अपील का भाग्य, हालांकि संशोधन अधिनियम के समय से पहले, उसी की वैधता पर भी निर्भर करेगा, और तदनुसार उक्त रिट याचिका के साथ निपटाया जा रहा है।

इस स्तर पर सामग्री का हवाला देना उचित होगा।

चुनौती के तहत प्रावधान। 1992 के संशोधन अधिनियम की धारा 2 इस प्रकार हैः

" 2. धारा 3 का संशोधन। उड़ीसा की धारा 3 में प्रशासनिक सेवा, वर्ग-II (अधिकारियों की नियुक्ति)

विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1987 का 8 (इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित), उप-धारा (2) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा होगी -

प्रतिस्थापित, अर्थात्ः

' (2) (क) विलय भर्तियों की इतनी संख्या जो होती

भर्ती वर्ष 1972 और 1973 में पदोन्नति के हकदार

उड़ीसा प्रशासनिक सेवा, वर्ग-II (भर्ती) नियम, 1959 के नियम 10 के तहत परिकल्पित प्रतिशत के आधार पर संगणित, संबंधित वर्षों के पदोन्नत व्यक्ति माने जाएंगे।

और विलय नियुक्तियों की वरिष्ठता का निर्धारण इसलिए

पदोन्नति पाने वाले माने जाते हैं,

(i) वर्ष 1972 का बनाम उड़ीसा प्रशासनिक सेवा, वर्ग-II में पी. के. डी. ए. एस. बनाम में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारी।

राज्य [खरे, सी. जे.]

313

भर्ती वर्ष 1972 के संबंध में; और

((ii) वर्ष 1973 की ओर से उड़ीसा में नियुक्त अधिकारियों की ओर से

प्रशासनिक सेवा, वर्ग-II में सीधी भर्ती द्वारा भर्ती वर्ष 1973 का सम्मान;

उसी सिद्धांत के अनुसार होगा जिसका पालन किया जाता है प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच अंतर वरिष्ठता का निर्धारण और

उड़ीसा प्रशासनिक सेवा के संबंध में पदोन्नति,

भर्ती वर्ष 1970 और 1971 के संबंध में श्रेणी-II और

उन्हें तदनुसार श्रेणीकरण सूची में रखा जाएगाः

(ख) शेष विलय भर्तियों को नीचे रखा जाएगा

श्रेणीकरण सूची में वर्ष 1973 की सीधी भर्तियाँ '।

इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले को

24.10.1996 दिनांकित आदेश द्वारा पाँच न्यायाधीश। हालाँकि, संविधान पीठ ने दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा इसे इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखना उचित समझा। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने नित्यानंद कर (ऊपर) में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए मामले को फिर से पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया। इस तरह यह मामला हमारे सामने है।

याचिकाकर्ताओं और अपीलकर्ताओं ने, अस्वाभाविक रूप से नहीं, स्थान देने की मांग की है

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर व्यापक निर्भरता, जिसने पहले वर्तमान मामले पर विचार किया। इसके क्रम में चार प्रमुख कारण बताए गए हैं, जो नित्यानंद कर (सुप्रा) के साथ संघर्ष को चित्रित करते हैं। आदेश के भौतिक भाग का हवाला देना उचित होगा, जो विचलन के प्रमुख बिंदुओं से संबंधित हैः

" हम इस अदालत के फैसले के माध्यम से लिया गया है

पक्षों के विद्वान वकील द्वारा नित्यानंद कर का मामला। अत्यंत सम्मान के साथ, हम तर्क से सहमत नहीं हैं और

उसमें निष्कर्ष निकाले गए। उक्त तक पहुँचने के हमारे कारण

निष्कर्ष इस प्रकार हैंः

(1) विलय से पहले, ओ. ए. एस. वर्ग II में भर्ती थी

नियमों के तहत चार अलग-अलग स्रोतों से। विलय के बाद,

सेवा में नियुक्ति केवल प्रत्यक्ष के माध्यम से सीमित थी

भर्ती। एकीकृत संवर्ग में 'वर्ष' की अवधारणा

आबंटन 'अव्यवहारिक हो गया था।

314

(2) विलय आदेश में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि O.S.A.S के सदस्य नए संवर्ग में O. A. S. के सदस्यों से जूनियर रैंक के होंगे। पद होने के कारण, एकीकृत संवर्ग में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त लोगों को उन लोगों से नीचे रखा जाना है जो O.S.A.S सेवा के मूल सदस्य थे। (3) प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री सुधीर चंद्र अग्रवाल ने हमें राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे के माध्यम से लिया है जिसमें यह विवादित नहीं है कि ओ. ए. एस. कक्षा II में किसी भी रिक्ति के संबंध में कोई विज्ञापन नहीं था। विज्ञापन वित्तीय सेवा और पुलिस सेवा से संबंधित था। विलय के बाद विज्ञापित या पहचानी गई रिक्तियां

संवर्गों को निर्दिष्ट किसी भी तरीके से भरा नहीं जा सका

प्रत्यक्ष भर्ती को छोड़कर सेवा नियम। (4) कि किसी भी मामले में, नए संवर्ग में नियुक्ति जो 21 दिसंबर, 1973 को गठित की गई थी, संवर्ग के गठन से पहले की तारीख से प्रभावी नहीं हो सकती थी, भले ही रिक्तियां उस तारीख से पहले मौजूद हों क्योंकि उक्त रिक्ति

1

एकीकृत संवर्ग में एक रिक्ति मानी जाएगी।

इसलिए हम निर्देश देते हैं कि इन मामलों को इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाए। रजिस्ट्री इस संबंध में उचित आदेशों के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखेगी

मामला "।

शुरुआत में यह ध्यान दिया जा सकता है कि दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा चित्रित चार कारणों में से किसी में भी वर्ष के सिद्धांत में त्रुटि नहीं पाई गई स्वयं का आवंटन। बल्कि, न्यायालय द्वारा दिए गए इन कारणों में से प्रत्येक के माध्यम से सामान्य सूत्र यह है कि आवंटन के वर्ष की अवधारणा को दिसंबर 1973 के विलय प्रस्ताव के माध्यम से अव्यवहारिक और अनुचित बना दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि दिसंबर 1973 के विलय का प्रभाव यह है कि एकीकृत संवर्ग में नियुक्ति पूरी तरह से सीधी भर्ती के माध्यम से होगी, जबकि विलय से पहले, ओ. ए. एस. वर्ग II में भर्ती चार अलग-अलग स्रोतों में से किसी एक द्वारा हो सकती है। इस मामले में, आवंटन के वर्ष का सिद्धांत अब अनावश्यक था और इसका आवेदन अनावश्यक था। उड़ीसा प्रशासनिक सेवा वर्ग II (भर्ती) नियमों का नियम 4 भर्ती की विधि से संबंधित हैः

(क) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती; (ख) उड़ीसा के सदस्यों के बीच से पदोन्नति

अधीनस्थ प्रशासनिक सेवा; और

(ग) ऐसी अन्य सेवाओं या पदों से स्थानांतरण जो तुलनीय हों।

उड़ीसा प्रशासनिक सेवा के साथ जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है समय-समय पर सरकार द्वारा;

(व्याख्या तुलनात्मक सेवा या डाक का अर्थ है कोई भी सेवा।

जिम्मेदारियाँ और परिलब्धियाँ जिनसे जुड़ी हैं - सरकार द्वारा प्रकृति में तुलनीय घोषित

डिप्टी कलेक्टर का पद)

((घ) चयन; और (ङ) उन व्यक्तियों का स्थानांतरण या पदोन्नति जिन्हें उपयुक्त माना जाता है।

सेवा में नियुक्ति के लिए

आर. 9 "के प्रावधान।

यह स्पष्ट है कि न तो दिसंबर का सरकारी संकल्प

1973 न ही 1992 के संशोधन अधिनियम की विवादित धारा 2 ने 1959 के भर्ती नियमों को स्पष्ट रूप से या निहित रूप से निरस्त किया है। वास्तव में, प्रस्ताव स्वयं प्रासंगिक नियमों की ओर इशारा करता है, जिससे 1959 के भर्ती नियमों के निहित निरसन की संभावना समाप्त हो जाती है। इसी तरह, 1973 के प्रस्ताव में किसी भी तरह से उप-कलेक्टरों की भर्ती को समाप्त करने या भर्ती के वैकल्पिक तरीके का प्रावधान नहीं था, इस मामले में यह नहीं माना जा सकता है कि इसका प्रभाव 1959 के भर्ती नियमों में निहित प्रावधानों को पूरी तरह से निरस्त करना था। यह 1978 तक नहीं था कि 1959 के भर्ती नियमों को उड़ीसा प्रशासनिक सेवा भर्ती नियम और पदोन्नति और प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए विनियम, 1978 के लागू होने के कारण निरस्त कर दिया गया था।

इसलिए हम खुद को प्रस्तुत किए गए निवेदन से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील द्वारा इस प्रभाव के लिए कि सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2003] एस. पी. पी.

4 एस सी आर।

316

1973 का प्रस्ताव उस समय लागू 1959 के भर्ती नियमों का एक निहित निरसन है।

बल्कि, के विवाद के संदर्भ में भौतिक प्रश्न

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि क्या 1973 का संकल्प 1959 के नियमों के नियम 4 में निहित प्रावधान को अनावश्यक और इस तरह से अमान्य बनाता है कि ओ. ए. एस. II में नियुक्ति केवल अन्य सभी स्रोतों को छोड़कर सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती है।

लेकिन उपखंड (ग) के संदर्भ में अन्य सेवाओं से स्थानांतरण, उपखंड (घ) के संदर्भ में चयन और 1959 के भर्ती नियमों के नियम 4 के उपखंड (ङ) के संदर्भ में धारा 9 के अनुसार स्थानांतरण या पदोन्नति तक सीमित नहीं है। यह मानते हुए भी कि विलय के तुरंत बाद की अवधि में ऐसी कोई समानांतर सेवा या संवर्ग मौजूद नहीं था, 1973 में विलय के बावजूद, विधानमंडल के लिए ऐसी और सेवाएं बनाने के लिए हमेशा खुला रहेगा, जिससे ओ. ए. एस. II को हस्तांतरण किया जा सकता था। तब, विलय के परिणामस्वरूप 1973 के प्रस्ताव का कानूनी प्रभाव केवल यह था कि 1959 के भर्ती नियमों के नियम 4 के उपखंड (बी) में कोई आवेदन नहीं था, और तब इसे निहित रूप से निरस्त माना जा सकता था। यह कहना और भी गलत है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने किया है, कि संवर्गों के एकीकरण के आधार पर, आवंटन के वर्ष का सिद्धांत था

अप्रासंगिक और अप्रासंगिक बना दिया। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, ऐसे कई स्रोत बने रहे जिनसे ओ. ए. एस. II में भर्ती अन्य तुलनीय सेवाओं से हस्तांतरण सहित विलय के बाद की जा सकती थी। किसी भी स्थिति में, भले ही यह माना जाए कि सीधी भर्ती अब भर्तियों का एकमात्र स्रोत होगी, जब तक कि ऐसी रिक्तियां थीं जिनकी पहचान विलय प्रस्ताव के लागू होने से पहले की गई थी, लेकिन जो बनी रहीं। अपूर्ण, आवंटन के वर्ष की अवधारणा वास्तव में लागू रही, हालांकि पहले की तुलना में अधिक सीमित रूप में।

आवंटन के वर्ष की अवधारणा स्पष्टीकरण द्वारा प्रदान की गई है।

उड़ीसा प्रशासनिक सेवा वर्ग II के नियम 4 (2) में निहित

(पदोन्नति, स्थानांतरण और चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1959 निम्नलिखित शर्तों में:

" इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, उड़ीसा प्रशासनिक सेवा के सदस्य के संबंध में आवंटन के वर्ष का अर्थ है 317 में वर्ष।

पी. के. डीएएस बनाम राज्य [खरे, सी. जे.]

जिसके संबंध में सरकार ने उड़ीसा प्रशासनिक सेवा के कैडर में एक रिक्ति को भरने का निर्णय लिया है जिसके खिलाफ सदस्य को दिखाया गया है।

यह निवेदन कि आवंटन के वर्ष के सिद्धांत को अव्यवहारिक माना जाना चाहिए, निश्चित रूप से इस तर्क से बिल्कुल अलग है कि आवंटन के वर्ष का सिद्धांत अपने आप में अनुचित है और,

इसलिए, कानून में बुरा। आम तौर पर, और निश्चित रूप से, हम रोशन लाल टंडन बनाम के अनुरूप विचारशील राय रखते हैं। भारत संघ, [1968] 1 एस. सी. आर. 185 और इस न्यायालय के अन्य निर्णय, कि यह वास्तविक सेवा की अवधि है जो निम्नलिखित मामलों में निर्धारक कारक होनी चाहिएः

पदोन्नति और परिणामी वरिष्ठता। हालाँकि, इस न्यायालय ने बाद में डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन मामले (उपरोक्त) में अपने निर्णय के आधार पर इस सामान्य नियम के लिए एक अलग अपवाद बनाया है, जिसमें कहा गया है कि जहां कई लोगों की वरिष्ठता और निहित अधिकार वर्षों की अभ्यस्त प्रथा के माध्यम से एक नियम के अस्तित्व पर निर्भर हो जाते हैं, तो यह नियम, यदि कुछ लोगों के अधिकारों के लिए हानिकारक है, तो इसे तब तक तुच्छ नहीं माना जाएगा, जब तक कि यह अव्यवहारिक या स्पष्ट रूप से मनमाना या गंभीर न हो।

डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन (उपरोक्त) में संविधान पीठ द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियां तत्काल मामले के संदर्भ में विशेष रूप से उपयुक्त हैंः

: " 47 (जे) सावधानीपूर्वक विचार के बाद किसी विशेष सेवा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए न कि किसी संभावित त्रुटि का पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिए। किसी स्थिर स्थिति को अस्थिर करना सेवा के हित में नहीं है।

(के) कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक आवेदन द्वारा उठाए गए विवाद को प्रतिरोध के सिद्धांतों द्वारा वर्जित माना जाना चाहिए।

न्यायपालिका यदि इसका निर्णय पहले किसी सक्षम अदालत द्वारा एक निर्णय द्वारा किया गया है जो अंतिम हो गया है।

इस न्यायालय ने नित्यानंद कर (उपरोक्त) मामले में, हमारे विचार में, सीधी भर्ती में संविधान पीठ के पूर्व निर्णय पर सही ढंग से भरोसा किया है। द्वितीय श्रेणी इंजीनियरिंग अधिकारी संघ (उपरोक्त), समय के भारी अंतराल और आवंटन के वर्ष की अवधारणा के अनुप्रयोग से जुड़ी प्रथा की लंबे समय से स्थापित पवित्रता पर विचार करते हुए।

नित्यानंद कर (उपरोक्त) के साथ टकराव व्यक्त करने वाले दोनों न्यायाधीशों की पीठ के आदेश द्वारा प्रदान किया गया दूसरा आधार, जिसे बाद में गठित तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था, और जिस पर वर्तमान में याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किया जाता है, वह यह है कि विलय आदेश में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि O.S.A.S के सदस्य नए संवर्ग में O. A. S. के सदस्यों से कनिष्ठ रैंक के होंगे। पद होने के कारण, एकीकृत संवर्ग में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त लोगों को उन लोगों से नीचे रखा जाना चाहिए जो O.S.A.S सेवा के मूल सदस्य थे।

हमने आवंटन के वर्ष के सिद्धांत की वैधता को बनाए रखने के लिए अपने कारणों को ऊपर रेखांकित किया है, जिसमें प्रमुख हमारी अनिच्छा है। डायरेक्ट रिक्रूट इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय में निहित आदेश को देखते हुए एक तय की गई प्रथा के साथ छेड़छाड़ करना। आबंटन वर्ष की अवधारणा को भी व्यवहार्य दिखाया गया है, क्योंकि 1973 के विलय के बाद के परिदृश्य में सरकार के लिए विभिन्न स्रोतों से अधिकारियों की भर्ती के लिए खुला था, जिसमें तुलनीय सेवाओं से स्थानांतरण भी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। जब एक बार आवंटन के वर्ष की अवधारणा को बरकरार माना जाता है, तो यह मायने नहीं रखता है कि O.S.A.S का पहला नाम पूर्ववर्ती O. A. S. के अंतिम नाम से तुरंत नीचे होगा। तथ्य की भौतिक बात यह है कि एक कानूनी कल्पना को अपनाने और संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपने संवैधानिक कार्य का सहारा लेने के माध्यम से, उड़ीसा राज्य के राज्यपाल ने वर्ष 1975 में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें दिसंबर 1973 के विलय प्रस्ताव के लागू होने से पहले वर्ष 1973 में पहचानी गई रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था। इस मामले में, आवंटन के वर्ष की कानूनी कल्पना 1975 में नियुक्त लोगों के संबंध में इस तरह काम करेगी जैसे कि उन्हें उस वर्ष नियुक्त किया गया था जब रिक्तियों की शुरुआत में पहचान की गई थी। दूसरे शब्दों में, उन्हें ओ. ए. एस. II के O.S.A.S के साथ विलय से पहले वर्ष 1973 में नियुक्त किया गया माना जाएगा, हालांकि उनकी सेवा की वास्तविक अवधि 1975 में ही शुरू होती देखी गई थी।

हम इस तथ्य की ओर इशारा करने के लिए भी विवश हैं कि विलय प्रस्ताव के आधार पर 1959 के नियमों में निहित पदोन्नति के सिद्धांत को इस तरह बरकरार रखा गया था कि किसी विशेष वर्ष के पदोन्नत लोगों को उस वर्ष की प्रत्यक्ष भर्तियों से अधिक वरिष्ठता दी जाएगी। यह O.S.A.S के वे सदस्य हैं, जैसे कि वर्तमान याचिकाकर्ता, जो वर्षों में O.S.A.S से पहले उनके मामले आने पर पदोन्नति हासिल करने में असमर्थ थे। विलय प्रस्ताव (1970-73) से पहले, जो पी. के. डी. ए. एस. बनाम पर वरिष्ठता चाहते हैं।

एकीकृत के सदस्य होने के मात्र तथ्य से भर्ती

. हमारी सुविचारित राय में, इस तरह का थोक एकीकरण नहीं हो सकता है

पूरे O.S.A.S के प्रचार के रूप में। यह अनुमान है

के भर्ती नियमों में निहित विभिन्न प्रावधानों द्वारा

मुख्यतः नियम 10 (7) और नियम 11।

यूले 10 (7) निम्नलिखित रूप में प्रदान करता हैः

" पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा सेवा में भर्ती के लिए या

चयन, इन नियमों के तहत, राज्य सरकार परामर्श करेगी

नियुक्ति से पहले आयोग।

यू. एल. 11 वरिष्ठता के आवंटन के सवाल से संबंधित हैः

" 11. वरिष्ठताः - (1) सी. एल. एस. के अधीन सेवा में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता। (ए), (बी), (सी) और (डी) आर 4 के किसी भी मामले में वर्ष निम्नलिखित क्रम में होगा, अर्थात्ः

(क) सी. एल. के अधीन पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त अधिकारी। (ख)

आर. 4 का, उनके नामों के क्रम में क्रमबद्ध किया गया।

आयोग द्वारा व्यवस्थित;

(ख) अन्य से स्थानांतरण द्वारा सेवा में नियुक्त अधिकारी

सी. एल. के तहत पदों की सेवा या सेवाएं। (ग) आर. 4 का, अंतर श्रेणी में

से उस क्रम में जिसमें उनके नाम व्यवस्थित किए गए हैं

आयोग;

(ग) सी. एल. के अधीन चयन द्वारा सेवा में नियुक्त अधिकारी।

((घ) आर. 4 का क्रम उस क्रम में है जिसमें उनके नाम हैं।

आयोग द्वारा व्यवस्था की जाती है;

(घ) प्रतिस्पर्धात्मक परिणाम पर सेवा में नियुक्त अधिकारी

सी. एल. के अनुसार परीक्षा। (ए) आर. 4 का, अंतर श्रेणी में

से उस क्रम में जिसमें उनके नाम व्यवस्थित किए गए हैं

आयोग "।

दिसंबर 1973 का विलय विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है।

पदोन्नति के लिए, इसे थोक पदोन्नति नहीं माना जा सकता है।

O.S.A.S. कर्मचारी। उक्त कर्मचारी जो सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2003] एस. यू. पी. में एकीकृत थे।

320

ओ. ए. एस. II, बल्कि, स्वयं के लिए एक वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए, लाभार्थी, जैसा कि वे हैं, एक ही उपाय के परिणामस्वरूप दोनों कैडरों का एकीकरण होता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत, राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसी सेवाओं और पदों पर भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने का अधिकार है, जब तक कि उस संबंध में विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रावधान नहीं किया जाता है। जैसा कि न्यायालय ने नित्यानंद कर मामले में ठीक ही कहा है

(उपर्युक्त), विधायिका या राज्य का राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, अपने विवेकाधिकार पर, वरिष्ठता का अधिकार प्रदान या विच्छेद कर सकता है। यह है। अनिवार्य रूप से नीति का विषय है और निहित अधिकार का प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि राज्य ऐसे किसी भी प्रत्यक्ष अधिकार को बदल या अस्वीकार कर सकता है, यहां तक कि पूर्वव्यापी प्रभाव के माध्यम से भी, यदि वह चाहे तो या सार्वजनिक हित में।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि ओ. ए. एस. वर्ग II में किसी भी रिक्ति के संबंध में कोई विज्ञापन नहीं था, और इस तथ्य के बावजूद कि उस वर्ष के विज्ञापन केवल वित्तीय सेवा और पुलिस सेवा के संबंध में थे, 1973 को उनके आवंटन वर्ष के रूप में सीधे भर्ती किए गए ओ. ए. एस. II को नियुक्त किया गया था। नित्यानंद कर मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर विचार नहीं किया था (ऊपर) क्योंकि इसे उच्च न्यायालय के समक्ष पहली बार में नहीं दबाया गया था। और इस तरह, रचनात्मक रेस जुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। वर्तमान कार्यवाही में पक्षकारों के कुछ अलग होने के कारण, इस मुद्दे को अब इस न्यायालय के समक्ष वैध रूप से उठाया जा सकता है।

हम इस दावे से खुद को असंतुष्ट पाते हैं कि वर्ष 1975 में भर्ती के लिए विज्ञापन में ओ. ए. एस. II की चूक, जिसमें केवल उड़ीसा वित्तीय और पुलिस सेवाओं में रिक्तियों का उल्लेख किया गया था, उत्तरदाताओं की सीधी भर्तियों की नियुक्तियों को रद्द करने का काम करेगी। जैसा कि नित्यानंद कर के मामले (ऊपर) में उचित रूप से देखा गया है, हालांकि इस आधार को न्यायालय द्वारा रचनात्मक न्यायपालिका के नियम को लागू करने के माध्यम से सीमा पर खारिज कर दिया गया था, कि आम तौर पर यह प्रतियोगी परीक्षा ओ. ए. एस. के लिए भी आयोजित एक सामान्य परीक्षा थी। विज्ञापन जारी होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी उम्मीदवार ने चयन का निहित अधिकार हासिल नहीं किया है। इसके विपरीत, जब एक बार सरकार द्वारा वर्ष 1973 के लिए रिक्तियों की पहचान की गई थी, तो वह एक समय पर और अपनी पसंद के तरीके से एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र थी। सामान्य परीक्षा पिछले वर्षों में उड़ीसा प्रशासनिक सेवा के साथ-साथ उड़ीसा वित्तीय सेवा और पी. के. डी. ए. एस. बनाम के लिए आयोजित की गई थी।

उड़ीसा पुलिस सेवा। तब, इस उद्देश्य के लिए जारी विज्ञापन में O.A.S.II की चूक का मात्र तथ्य अपने आप में प्रत्यर्थी प्रत्यक्ष भर्तियों की नियुक्तियों को निरर्थक के रूप में प्रस्तुत करने के बराबर नहीं होगा। उड़ीसा राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि सामान्य प्रथा रिक्तियों की एक काल्पनिक संख्या की पहचान करना है, जो तब हो सकती है

वास्तविक भर्ती के समय या तो अधिक या अपर्याप्त सेवन से समझौता, उम्मीदवारों की क्षमता जैसे कारकों पर निर्भर करता है

और उस समय सरकार की विशेष आवश्यकताएँ। इसी तरह के कारणों से उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने अनंत कुमार बोस (उपरोक्त) में विरोधी पक्षों की नियुक्ति को बरकरार रखा, हालांकि रिक्तियों के संदर्भ में मूल रूप से परिकल्पित की तुलना में कई अधिक भर्तियों की नियुक्ति की गई थी।

नित्यानंद कर (ऊपर) के बीच संघर्ष का चौथा और अंतिम आधार

और प्रदीप चंद्र परिजा इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए चौथे कारण में अभिव्यक्ति पाते हैं कि वे पहले के उदाहरण में पहुंचे निष्कर्षों से असहमत हैं।

न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" कि किसी भी मामले में, नए संवर्ग में नियुक्ति जो थी

21 दिसंबर, 1973 को गठित किया गया; प्रभाव से नहीं बनाया जा सका

कैडर के गठन से पहले की तारीख से, भले ही

उस तारीख से पहले रिक्तियां मौजूद थीं क्योंकि उक्त रिक्ति

एकीकृत संवर्ग में एक रिक्ति मानी जाएगी।

अत्यंत सम्मान के साथ, हम खुद को सहमत होने में असमर्थ पाते हैं

उपरोक्त अवलोकन। वास्तव में, यह अवलोकन एक और समान है

यह अवलोकन कि "आवंटन के वर्ष" की अवधारणा अव्यवहारिक हो गई थी ", जिनका हम पहले ही खंडन कर चुके हैं। दोहराना, तथ्य के आधार पर

कि 21 दिसंबर, 1973 को प्रभावी विलय से पहले ओ. ए. एस. II में रिक्तियों की पहचान की गई थी, इन रिक्तियों को निश्चित रूप से एकीकृत संवर्ग में रिक्तियों के रूप में माना जाएगा। एक बार

आवंटन के वर्ष की अवधारणा को वैध माना जाता है, हम इसके अलावा किसी अन्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि ऐसी रिक्तियों की पहचान पहले की गई थी

विलय प्रस्ताव सरकार द्वारा अपने विवेक से भरा जाएगा,

21 दिसंबर, 1973 को प्रभावी विलय के बावजूद।

वर्ष प्रदान करने के उद्देश्य से एक कानूनी कथा बनाई गई थी

आवंटन। इस तरह की कानूनी कल्पना को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए।

भावनगर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2003] में। 4 एस सी आर।

322 विश्वविद्यालय वी. पालिताना शुगर मिल प्रा. लि. लिमिटेड और अन्य, [2003] 2 एस. सी. सी. 111, कानून निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित किया गया हैः

" कानून में एक कानूनी कल्पना बनाने का उद्देश्य और उद्देश्य सर्वविदित है। जब एक कानूनी कल्पना बनाई जाती है, तो इसका पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कं. लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल, [1951] 2 All.E.R 587, लॉर्ड एस्क्विथ, जे. ने निम्नलिखित शब्दों में कानून का उल्लेख कियाः

" यदि आपको किसी काल्पनिक स्थिति को वास्तविक मानने के लिए कहा जाता है, तो आपको निश्चित रूप से, जब तक कि ऐसा करने से मना न किया जाए, ऐसा करना चाहिए।

उन परिणामों और घटनाओं की भी वास्तविक रूप से कल्पना करें जो, यदि अनुमानित स्थिति वास्तव में मौजूद थी, तो अनिवार्य रूप से इससे निकली होंगी या इसके साथ आई होंगी। इस मामले में इनमें से एक 1939 के किराए के स्तर से मुक्ति है। कानून कहता है कि आपको एक निश्चित स्थिति की कल्पना करनी चाहिए; यह नहीं कहता है कि ऐसा करने के बाद, जब अपरिहार्य स्थिति की बात आती है तो आपको अपनी कल्पना को चौंका देना चाहिए या अनुमति देनी चाहिए।

उस स्थिति के परिणाम "।

उक्त सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा एम में दोहराया गया है। वेणुगोपाल बनाम. प्रभागीय प्रबंधक, जीवन बीमा निगम

भारत, मछलीपट्टनम, एपी और ए. एन. आर. , [1994] 2 एससीसी 323। यह भी देखें

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 4 v. कारखानों के मुख्य निरीक्षक & ओआरएस। , [1998] 5 एस. सी. सी. 738, वोल्टास लिमिटेड, बॉम्बे बनाम। भारत संघ और अन्य। , [1995] सप. 2 एस. सी. सी. 498, हरीश टंडन बनाम एडल्ट। जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद, यू. पी. और अन्य। , [1995] 1 एस. सी. सी. 537

और जी. विश्वनाथन आदि। माननीय अध्यक्ष, तमिलनाडु विधान सभा, मद्रास और अन्न। , [1996] 2 एससीसी 353 "।

आबंटन के उद्देश्यों के लिए विलय प्रस्ताव का प्रभाव

वरिष्ठता के लाभ केवल यह थे कि O.S.A.S के पूर्व सदस्य अब उन प्रत्यक्ष भर्तियों से वरिष्ठ के रूप में रैंक करेंगे जिनका सेवा में शामिल होने का वर्ष और आवंटन का वर्ष 1973 से बाद का था। दूसरे शब्दों में, दिसंबर 1973 में विलय के समय, O.S.A.S के उप-कलेक्टरों को न केवल पूर्ववर्ती O. A. S. II के उप-कलेक्टरों के नीचे की श्रेणीकरण सूची में रखा गया था, बल्कि उन अधिकारियों के नीचे भी रखा गया था जिनकी परिकल्पना पिछले वर्षों की रिक्तियों द्वारा की गई थी, लेकिन जो अभी तक P. K. DAS v. थे।

वास्तव में भर्ती किया जाना। जैसा कि हमारे द्वारा ऊपर कहा गया है, विलय का उद्देश्य स्वयं ओ. ए. एस. II में सीधी भर्ती को बंद करना नहीं था, न ही यह चिन्हित रिक्तियों के प्रश्न को संबोधित करता था।

हम यह अनुमान लगाने के लिए मजबूर हैं कि रिक्तियों की पहचान की गई है

वर्ष 1973, और दिसंबर के विलय प्रस्ताव से पहले के अन्य वर्ष

1973 , अस्तित्व में रहा और सरकार द्वारा उचित रूप से भरा गया

नित्यानंद कर के मामले (उपरोक्त) में न्यायालय द्वारा यह उचित ही कहा गया है कि न्याय के हित में इस तथ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी प्रत्यक्ष भर्तियों की संख्या की तुलना में कम है। सैकड़ों विलयवादी जो निष्क्रिय O.S.A.S से संबंधित थे। उत्तरदाताओं को बहुत नुकसान होगा यदि उन्हें श्रेणीकरण सूची में विलय भर्तियों से नीचे रखा जाता है, जबकि विलयवादी शायद ही उनके ऊपर रखी गई सीधी भर्तियों की छोटी संख्या से प्रभावित होते हैं। किसी भी स्थिति में, 1959 के भर्ती नियम अपने आदेश में स्पष्ट हैं कि केवल एक विशेष वर्ष के पदोन्नत लोगों को उस वर्ष की सीधी भर्तियों से ऊपर रखा जाना है। वर्तमान याचिकाकर्ता जो केवल विलयवादी हैं, लेकिन प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार पदोन्नति नहीं देते हैं, वे पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं, और इसलिए, उन्हें सीधे भर्तियों से नीचे के पदों पर रखा गया है, जिसका आवंटन वर्ष 1973 था।

प्रत्यक्ष भर्तियों के संबंध में कोई कानून मौजूद नहीं था। इससे पहले का आदेश कार्यकारी निर्देश के कारण जारी किया गया था जिसे मान्यता दी गई थी

वरिष्ठता मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि केवल एक नागरिक अधिकार है। इस मामले में वरिष्ठता का अधिकार भी निहित या अर्जित अधिकार नहीं था। इस मामले में, याचिकाकर्ता ऐसे लाभ की मांग करते हैं जिसके वे अन्यथा हकदार नहीं हैं। हमारी राय में, विधायिका के पास एक उचित कानून पारित करने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र है जो इसकी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2003] एस. पी. पी. के साथ न्याय करेगा।

324

कर्मचारी। अन्यथा भी उस प्रभाव के लिए एक अनुमान लगाना होगा। यदि विवादित विधान के कारण संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है, तो इस न्यायालय के लिए इसे अधिकार से बाहर घोषित करने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि इससे याचिकाकर्ताओं को कुछ कठिनाई हो सकती है। एक वैध कानून को निरस्त करने के लिए केवल कठिनाई एक आधार नहीं हो सकती है जब तक कि इसे भेदभाव या अनुचितता से पीड़ित नहीं माना जाता है। इस प्रकार, किसी वैध कानून को तभी निरस्त किया जा सकता है जब वह पाया जाए।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार के बाहर होना और अन्यथा नहीं। हमें नहीं लगता कि इस मामले में संविधान का अनुच्छेद 14 आकर्षित करता है।

श्री भगत विद्वान वकील ने इस निर्णय पर पूरी तरह से भरोसा जताया

रोशन लाल टंडन (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का। उनके अनुसार, यह मामला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उक्त निर्णय से समाप्त होता है। श्री भगत ने उक्त निर्णय को उत्साहपूर्वक पढ़ा और फिर से पढ़ा। हमारा विचार है कि रोशन लाल टंडन के मामले पर विद्वान वकील की निर्भरता (ऊपर) पूरी तरह से गलत है। उक्त निर्णय में, एक संवर्ग में लाए गए पदोन्नत और प्रत्यक्ष भर्तियों को नियमों के एक समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो कि यहाँ एक मामला नहीं है।

नतीजतन, हम उड़ीसा प्रशासनिक की वैधता को बरकरार रखते हैं।

सेवा, वर्ग-II (अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन अधिनियम, 1992 और विशेष रूप से इसकी धारा 2, जो उचित रूप से प्रभावी करने का प्रयास करती है।

नित्यानंद कर (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के लिए।

तदनुसार रिट याचिका और अपील खारिज कर दी जाती है। वहाँ होगा,

हालाँकि, लागत के बारे में कोई आदेश न दें।

रिट याचिका और अपील खारिज कर दी गई।